खंड -6 अंक -06 जनवरी -2024

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

संदेश

दिसंबर में, जल क्षेत्र में गतिविधियों की भरमार देखी गई। के.ज.आ. के अधिकारी जल संबंधी परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा, तकनीकी विशेषज्ञ मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) ने राष्ट्रीय परियोजनाओं जैसे पोलावरम सिंचाई परियोजना, शाहपुरकंडी परियोजना के मुख्य मुद्दों को ध्यान मे रखते हुए प्रगति की सावधानीपूर्वक निगरानी की। अधिकारियों ने अपनी व्यापक समीक्षाओं के आधार पर परियोजना प्राधिकरण अधिकारियों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। मैंने स्वयं दूसरे रावी-ब्यास लिंक के पीएफआर को अंतिम रूप देने के लिए टीम का नेतृत्व किया। लखवार और रेणुका परियोजना से संबंधित कई डिज़ाइन मुद्दों को अंतिम रूप दिया गया।

एनडब्ल्यूडीए के अधिकारियों के साथ मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा (एमएसटीजी) लिंक परियोजना पर एक और महत्वपूर्ण संयुक्त दौरा किया गया।

सीडब्ल्यूसी ने सीडब्ल्यूसी और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के जल संसाधन/सिंचाई/जलशक्ति विभागों के बीच कार्यों में तालमेल बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ नियमित बातचीत शुरू की है। जल संसाधन से संबंधित गतिविधियों में तालमेल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के डब्ल्यूआरडी प्रतिनिधियों के साथ तीसरी तिमाही वार्ता आयोजित की गई।

जिसमें "मणिपुर की सेकमई नदी के किनारे बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी कार्य" पर एक उल्लेखनीय बैठक आयोजित की गई। यह चर्चा सक्रिय जल प्रबंधन रणनीतियों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए संरचनात्मक उपायों और नदी तट के विकास द्वारा बाढ़ सुरक्षा पर केंद्रित रही।

बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अनुसार, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की स्थापना राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.757(ई) दिनांक 17.02.2022 के माध्यम से की गई थी, जैसा कि अधिनियम की धारा 5(1) में उल्लिखित है। मुझे दिसंबर, 2023 के दौरान एनसीडीएस की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला।

बैठक के दौरान, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत तैयार किए जाने वाले विभिन्न मसौदा नियमों पर व्यापक चर्चा हुई, जिसके परिणामस्वरूप 7 नियमों को अंतिम रूप दिया गया और मंजूरी दी गई। इसके अलावा, बांध सुरक्षा प्रयासों को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, दो उप-समितियां भी स्थापित की गईं: बांध सुरक्षा प्रबंधन और निगरानी एवं इंस्ट्रुमेंटेशन।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, चरण- II और III के तहत पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान आने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए के.ज.आ. के अधिकारियों ने कर्नाटक में तीन बांधों- कृष्णराज सागर, अलमाटी बांध और तुंगभद्रा बांध का निरीक्षण किया।

किसी संगठन में युवा पेशेवरों का स्वागत करना हमेशा एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। नए सहायक निदेशकों को उनके प्रशिक्षण (24 अप्रैल 2023 से 8 दिसंबर 2023 तक आयोजित 33वां प्रवेशकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)) के पूरा होने के बाद विभिन्न कार्य सौंपे गए। हमने इन सहायक निदेशकों को नए विचारों को आत्मसात करने के लिए दो महीने के भीतर नई तकनीकों का लाभ लेकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रक्रियाओं के सुधार के बारे में विचार देने का काम सौंपा है।

प्रक्रियाओं में निरंतरता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज़ीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए, हमने सीडब्ल्यूसी इकाइयों को मौजूदा एसओपी का दस्तावेजीकरण करने और विभिन्न गतिविधियों की पहचान करने का निर्देश दिया है जहां मानकीकरण की आवश्यकता है लेकिन एसओपी तैयार नहीं किया गया है। सीडब्ल्यूसी के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लाभ हेतु ऐसी सभी गतिविधियों के एसओपी तैयार और संकलित की जाएगी।

आगामी वर्ष के दौरान कई गतिविधियों और नई पहलों की योजना बनाई गई है। हम सब मिलकर आने वाले वर्ष में सीडब्ल्यूसी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।

विषयसूची

एनडीएसए और डीआरआईपी

- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की तीसरी बैठक
- विश्व बैंक द्वारा डीआरआईपी-III तैयारी बैठक

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

- कालेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना
- पोलावरम सिंचाई परियोजना
- मुल्लापेरियार बांध
- सरहिन्द/राजस्थान फीडर
- जमरानी परियोजना, उत्तराखंड
- द्वितीय रावी-ब्यास लिंक परियोजना
- शाहपुरकंडी बांध परियोजना

वेबिनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण

- सीडब्ल्यूईएस (ग्रुप-ए) के लिए 33वाँ प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)
- विश्व बैंक द्वारा आयोजित दूसरा वेबिनार
- डीबीए पर प्रशिक्षण, बाढ़ मानचित्र, ईएपी आदि तैयार करना
- पर्यावरण एवं सामाजिक अभिमुखीकरण पर कार्यशाला

दौरा/निरीक्षण

- लखवार बहुउद्देशीय परियोजना
- कृष्णराज सागर, अलमाटी बांध और तुंगभद्रा बांध
- मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा (एमएसटीजी) लिंक परियोजना का संयुक्त दौरा

के.ज.आ. की अन्य गतिविधियाँ

i. बाढ़ और संबंधित मामले

- देश में बाढ़ की स्थिति-दिसंबर 2023

ii. अन्य गतिविधियाँ

- राज्यों के साथ तीसरी त्रैमासिक वार्ता बैठक
- मणिपुर के विधायक श्री रामेश्वर सिंह से मुलाकात
- पीएमकेएसवाई, एआईबीपी/सीएडीडब्ल्यूएम योजनाओं के पुनरुद्धार हेतु कार्य समूह की रिपोर्ट पर बैठक
- सैटेलाइट डेटा के उपयोग पर प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक

iii. राजभाषा संबन्धित

- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक
- हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

iv. जलाशय निगरानी

गैलरी

एनडीएसए और डीआरआईपी

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की तीसरी बैठक

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 5 (1) के तहत राजपत्र अधिसूचना एसओ 757 (ई) दिनांक 17.02.2022 के माध्यम से राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) का गठन किया गया है। एनसीडीएस की दो बैठकें क्रमश: 02.08.2022 और 06.06.2023 को आयोजित की गईं।

श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, के.ज.आ. और अध्यक्ष, एनसीडीएस और भारत सरकार के पदेन सचिव ने 05.12.2023 को राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की तीसरी बैठक की।

बैठक में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, के.ज.आ., एनडीएसए, एनडीएमए, सीएसआईआर-एनजीआरआई, एनआरएससी, जीएसआई, एचपीईआरसी, सीईए, एमओईएफ एंड सीसी, आईएमडी, डब्ल्यूआरडी आंध्रप्रदेश, डब्ल्यूआरडी हिमाचल प्रदेश, डब्ल्यूआरडी बिहार, डब्ल्यूआरडी मणिपुर, डब्ल्यूआरडी गुजरात, डब्ल्यूआरडी राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाने वाले विभिन्न मसौदा नियमों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। विचार-विमर्श के बाद, 7 नियमों को अंतिम रूप दिया गया और एनसीडीएस द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अलावा, बांध सुरक्षा प्रबंधन और निगरानी एवं उपकरण नामक दो उप-समितियों के गठन को भी अंतिम रूप दिया गया।

विश्व बैंक द्वारा डीआरआईपी-III तैयारी बैठक

सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ डीआरआईपी-3 की तत्परता/तैयारी पर चर्चा करने के लिए विश्व बैंक द्वारा 21.12.2023 को विश्व बैंक कार्यालय, नई दिल्ली में एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान, डीआरआईपी-III के लिए तत्परता मानदंडों को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की योजना पर चर्चा की गई है। बैठक में जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, विश्व बैंक और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया।

कालेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 01.12.2023 को अपने कक्ष में कालेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा ली गई बैठक में भाग लिया। बैठक में कालेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

पोलावरम सिंचाई परियोजना

पोलावरम सिंचाई परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के रामय्यापेटा गांव के पास गोदावरी नदी पर क्रियान्वित की जा रही है। इस बहुउद्देशीय प्रमुख परियोजना में 4.36 लाख हेक्टेयर की अंतिम सिंचाई क्षमता बनाने के लिए एक अर्थ कम रॉकफिल (ईसीआरएफ) बांध के साथ-साथ सैडल अर्थ बांध, एक स्पिलवे, सिंचाई सुरंग, नेविगेशन सुरंग और चैनल और दोनों किनारों पर दो मुख्य नहरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में 960 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन, 540 गांवों में पेयजल आपूर्ति और 84.7 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) पानी (नुकसान सहित) को कृष्णा बेसिन में मोड़ने की भी परिकल्पना की गई है।

आरसीसी के अनुसार 2013-14 पीएल पर परियोजना की लागत है 29027.95 करोड़ रुपये [पहली आरसीई (2010-11) के अनुसार मात्रा के लिए] और 2017-18 पीएल पर 47725.74 करोड़ रुपये [दूसरी आरसीई (2017-18 पीएल) के अनुसार संशोधित मात्रा के लिए]। पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिसंबर 2023 तक परियोजना की कुल प्रगति (कार्य, एलए और आर एंड आर सहित) 48.69% है। शुरुआत से लेकर 30.11.2023 तक परियोजना पर कुल व्यय 21206.96 करोड़ रुपये (एनपी के तहत 16476.25 करोड़ रुपये) है। परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के बाद भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को दिसंबर 2023 तक कुल 15112.738 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) की स्थिति की समीक्षा के लिए 5 दिसंबर, 2023 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने की, जिसमें माननीय मंत्री (जल शक्ति) के सलाहकार और जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, केंद्रीय जल आयोग, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए), सीएसएमआरएस और मैसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस के अधिकारी शामिल हुए।

अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कॉफ़रडैम में रिसाव के मुद्दों, डी-वॉल और वाइब्रो स्टोन कॉलम के निर्माण, विशेषज्ञ डिजाइन एजेंसी और व्यक्तिगत विशेषज्ञों की नियुक्ति: चरण- I के लिए संशोधित लागत अनुमान: निर्माण चरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर: 2023-24 के कामकाजी मौसम के लिए कार्य योजना, स्पिलवे गेटों को बंद करना और जलाशय को जब्त करना आदि पर चर्चा हुई।

मुल्लापेरियार बांध

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 04.12.2023 को के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा के कक्ष में उनके द्वारा ली गई बैठक में भाग लिया। बैठक में मुल्लापेरियार बांध को मजबूत करने के उपायों सहित इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

सरहिन्द/राजस्थान फीडर

01.12.2023 को सचिव, डीओडब्ल्यूआर की अध्यक्षता में राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, के.ज.आ. और पंजाब सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया।

पंजाब सरकार के जल संसाधन प्रधान सचिव ने परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति के साथ-साथ बाधाओं/मुद्दों से अवगत कराया। परियोजना अधिकारियों द्वारा राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर के संबंध में मुद्दों को हल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया गया।

बताया गया कि राजस्थान फीडर के 96.65 किमी में से कुल 80.60 किमी रिलाइनिंग का कार्य पूरा हो चुका है। इसी प्रकार, सरहिंद फीडर की कुल 100.07 किमी में से 84 किमी की रीलाइनिंग पूरी हो चुकी है। दोनों नहरों में करीब 16 किमी रिलाइनिंग बाकी है। सरहिन्द फीडर के शेष हिस्से की रीलाइनिंग अगले समापन में प्रस्तावित है।

परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए विस्तृत चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि पंजाब सरकार राज्य परियोजना प्राधिकरणों द्वारा सुझाए गए डिजाइन के अनुसार राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर (आरएफ और एसएफ) परियोजना के निष्पादन के संबंध में साइड लाइनिंग (कंक्रीट लाइनिंग) लेकिन नीचे टाइल (ईंट टाइल) के साथ एक पायलट परियोजना शुरू करेगी।

यह भी निर्देश दिया गया कि के.ज.आ. तकनीकी रूप से इसकी जांच कर सकता है और पायलट के पूरा होने के 10 दिनों के भीतर विकल्प की तकनीकी व्यवहार्यता पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है।

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 19.12.2023 को सरहिंद/राजस्थान फीडर के संबंध में के.ज.आ. के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा के कक्ष में उनकी अध्यक्षता में ली गई बैठक में भाग लिया। बैठक में नहरों की साइड लाइनिंग की स्थिरता सहित परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

जमरानी परियोजना, उत्तराखंड

श्री संजय कुमार सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) ने 20.12.2023 को सम्मेलन कक्ष, तीसरी मंजिल, के.ज.आ. में जमरानी परियोजना, उत्तराखंड के लिए कंक्रीट/बांध के प्रकार की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के मुद्दे की जांच के लिए समीक्षा समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की। श्री विवेक त्रिपाठी, सीई डिज़ाइन (एन एंड डब्ल्यू), श्री समीर कुमार शुक्ला, निदेशक, बीसीडी (एन एंड डब्ल्यू), श्री एन.एस. शेखावत, निदेशक, सीएमडीडी (एन एंड डब्ल्यू) और के.ज.आ., सीएसएमआरएस, उत्तराखंड सरकार के अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में, सदस्य (डी एंड आर) ने तकनीकी व्यवहार्यता और लागत-प्रभावशीलता पर विचार करते हुए आरसीसी और सीवीसी के बीच चयन करने के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड राज्य सीएसएमआरएस और के.ज.आ. को फ्लाई-ऐश परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, आवृत्ति-आधारित मॉडलटाइम इतिहास विधियों का उपयोग करके गतिशील विश्लेषण करेगा जो सीवीसी और आरसीसी के लिए समान अनुभागों को अपनाएगा और परिणामों की तुलना करेगा और लागत अनुमानों की समीक्षा करेगा।

द्वितीय रावी-ब्यास लिंक परियोजना

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने इस संबंध में पिछली बैठकों के अनुसरण में 15.12.2023 को दूसरी रावी ब्यास लिंक परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) की प्रगति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की।

बैठक में डब्ल्यूआरडी, पंजाब सरकार (जीओपी), केंद्रीय जल आयोग और अन्य संबंधित संगठनों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान 12-14 दिसंबर, 2023 तक के.ज.आ. अधिकारियों द्वारा किए गए दौरे के आधार पर बैराज के डिजाइन पर विस्तृत चर्चा की गई।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने के.ज.आ. के डिजाइन विंग के अधिकारियों को डब्ल्यूआरडी, जीओपी को बैराज के डिजाइन पर विभिन्न विकल्प प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, डब्ल्यूआरडी, जीओपी के अधिकारी के.ज.आ. के विशेष निदेशालयों के साथ परामर्श करके परियोजना की लागत और लाभ तय कर सकते हैं और तदनुसार, पीएफआर को तुरंत अंतिम रूप दिया जा सकता है।

शाहपुरकंडी बांध परियोजना

शाहपुरकंडी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) रावी नदी पर है, जो रंजीत सागर बांध से 11 किमी नीचे की ओर और माधोपुर हेडवर्क्स से 8 किमी ऊपर की ओर है। इसमें 55.5 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध, नदी के बाएं किनारे पर 7.70 किमी लंबे हाइडल चैनल, 2 हेड रेगुलेटर, एक पंजाब में शाहपुरकंडी हाइडल चैनल (बायीं ओर) और दूसरा जम्मू-कश्मीर में रावी नहर (दाहिनी ओर) को फीड करने के लिए निर्माण की परिकल्पना की गई है।

इस परियोजना से 37173 हेक्टेयर (जम्मू-कश्मीर में 32173 हेक्टेयर + पंजाब में 5000 हेक्टेयर) का सिंचाई लाभ और 206 मेगावाट (2x99 मेगावाट + 8 मेगावाट) की बिजली क्षमता है।

मुख्य बांध की प्रगति खुदाई- 97.90% और कंक्रीटिंग-89% है, जबकि पावर हाउस के मामले में- 93.59% खुदाई का काम नवंबर, 2023 के अंत तक पूरा हो चुका है। अनुमोदित आरसीई के अनुसार परियोजना की लागत रु. अक्टूबर, 2022 पीएल पर 2715.70 करोड़।शुरुआत से नवंबर 2023 तक परियोजना पर कुल खर्च 2214.97 करोड़ रुपये है।

पंजाब में रावी नदी पर एसकेडीपी (एक राष्ट्रीय परियोजना) के कार्यान्वयन की देखरेख/निगरानी के लिए शाहपुरकंडी बांध परियोजना (एसकेडीपी) के लिए निगरानी समिति की 11वीं बैठक 07.12.2023 को निगरानी समिति के अध्यक्ष, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में बुलाई गई थी।

कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति (प्रत्येक घटक/मदवार), परियोजना के निर्धारित समापन के लिए शेष कार्यों के लिए कार्रवाई कार्यक्रम, लखनपुर बसोहली रोड के पुनर्संरेखण मुद्दों की स्थिति, नूरा पुल के निर्माण की वैधानिक मंजूरी, मुक्तेश्वर मंदिर की सुरक्षा, रावी नहर के प्रमुख नियामक, कश्मीर नहर के लिए सुखराल खड्ड साइफन पर एक्वाडक्ट, पनबिजली चैनल के पावर हाउस के सिविल कार्यों की प्रगति और जलाशय को अवरोधन करने की अनुसूची के के संबंध में चर्चा की गई।

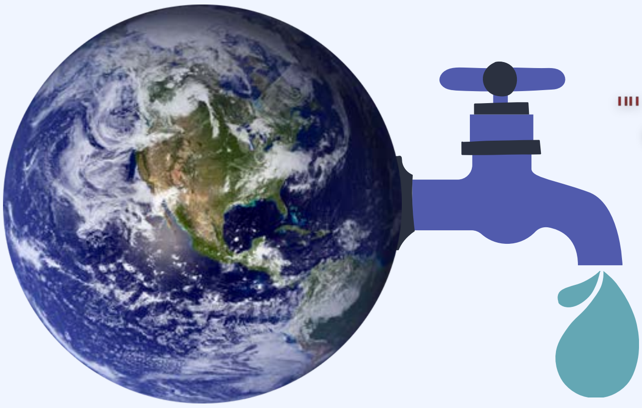

"आज बचाओ, कल बचाओ;
जल बचाओ, जीवन बचाओ!"

सीडब्ल्यूईएस (ग्रुप-ए) के लिए 33वाँ प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी)

प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम) संगठनों के भीतर एक महत्वपूर्ण पहल है, जो नए कर्मचारियों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। नवागंतुकों को विभागीय संस्कृति, नीतियों और कार्य वातावरण से परिचित कराने के लिए डिज़ाइन किया गया यह कार्यक्रम एक अच्छी तरह से तैयार और प्रेरित कार्यबल को आकार देने में एक महत्वपूर्ण निवेश का प्रतिनिधित्व करता है।

सीडब्ल्यूईएस (ग्रुप-ए) परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 33वां प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) 24.04.2023 को राष्ट्रीय जल अकादमी में शुरू हुआ, जो 8 महीने की व्यापक अवधि का था। इस आईटीपी में के.ज.आ. के कुल 10 सहायक निदेशकों ने भाग लिया। कार्यक्रम को कार्यालय प्रशासन और नीतियों, जल विज्ञान, जल विज्ञान डेटा प्रसंस्करण की तकनीक, बाढ़ पूर्वानुमान और प्रबंधन, बेसिन योजना और प्रबंधन, सिंचाई योजना, जल प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। एनईआरआईवाल, तेजपुर और आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई, रायपुर के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में फरक्का बैराज, टेहरी बांध परियोजना, पोलावरम परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में सर्वेक्षण और जांच स्थलों जैसी महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं के दौरे के माध्यम से परियोजना की सराहना भी की गई।

33वें आईटीपी का समापन 8 दिसंबर, 2023 को श्री नवीन कुमार, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), केंद्रीय जल आयोग और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समापन कार्यक्रम के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में श्री ए.के. खार्या, सीई (बीपीएमओ), डॉ.बी.आर.के.पिल्लई, सीई (एचआरएम), और श्री सुनील कुमार, निदेशक (प्रशिक्षण) वर्चुअल रूप में भाग लिया।

विश्व बैंक द्वारा आयोजित दूसरा वेबिनार

ऑस्ट्रेलियाई जल साझेदारी के सहयोग से वर्ल्ड बैंक द्वारा आयोजित दूसरा वेबिनार 8 दिसंबर, 2023, 11: 30–13: 00 बजे (IST) को आयोजित किया गया था, जो बाढ़ जोखिमों के प्रबंधन, लैंगिक समानता, विविधता और सामाजिक समावेशन पर केंद्रित था।

यह बांध सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विश्व बैंक द्वारा आयोजित ज्ञान विनिमय वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा है। इन वेबिनार का उद्देश्य भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायियों/पेशेवरों के बीच ज्ञान साझा करना और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखना है। चूंकि यह हमारी डीआरआईपी कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षण मंच और पिछले दस वर्षों से प्राप्त अपने अनुभव को व्यापक दर्शकों के साथ साझा करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

डीबीए पर प्रशिक्षण, बाढ़ मानचित्र, ईएपी आदि तैयार करना

डीआरआईपी चरण-II और III के तहत एफई एंड एसए निदेशालय, डीएसओ, सीपीएमयू द्वारा 'बांध टूटने का विश्लेषण,बाढ़ मानचित्रों की तैयारी,आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी),जलाशय रूटिंग और फ्री बोर्ड गणना' पर प्रशिक्षण हॉल,नए पुस्तकालय भवन में पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (11-15 दिसंबर 2023) आयोजित किया गया। 08 राज्यों (अर्थात् पंजाब, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश), 01 राज्य पीएसयू (यूपीजेवीएनएल) के कुल 34 अधिकारियों और आईआईएससी बैंगलोर के एमटेक छात्रों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

पर्यावरण एवं सामाजिक अभिमुखीकरण पर कार्यशाला

पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं के संबंध में अपेक्षित टेम्पलेट्स में जानकारी भरने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को मार्गदर्शन देने के लिए सीपीएमयू द्वारा 29.12.2023 को 11:00 बजे एक वर्चुअल अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना

डी एंड आर के सदस्य श्री संजय कुमार सिब्बल ने अपने नेतृत्व में के.ज.आ. अधिकारियों के एक समूह और यूजेवीएनएल, जीजीई, सीएसएमआरएस और एल एंड टी के अन्य अधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ 07.12.2023 को लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना (एमपीपी) के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। जिन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया उनमें मुख्य बांध स्थान, अपवर्तन संरचनाएं, विद्युत अंतर्ग्राही और विद्युतघर परिसर शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य लखवार एमपीपी से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करना था।

इसके बाद, 08.12.2023 को, साइट के दौरे के दौरान की गई टिप्पणियों पर चर्चा करने और लखवार एमपीपी के पहचाने गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए आगे की रणनीति बनाने के लिए देहरादून के उज्ज्वल भवन में एक बैठक हुई।

इसके अलावा, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड की स्थिति की समीक्षा के लिए सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण की अध्यक्षता में 12.12.2023 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग), श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई थी।

कृष्णराज सागर, अलमाटी बांध और तुंगभद्रा बांध

श्री एस.एस. बख्शी, निदेशक, डीएसआर, डीटीई/सीपीएमयू और श्री सौरभ शरण, उप निदेशक, डीएसआर डीटीई/सीपीएमयू और मेसर्स एसएमईसी ईएम कंसल्टेंट्स के विशेषज्ञ जिसमें श्री आर्थर यापा, टीएल, श्रीमती नीता अरोड़ा डीटीएल, श्री हनी स्लेम डैम शामिल हैं। डिजाइन विशेषज्ञ, एचएम विशेषज्ञ ने 11 से 14 दिसंबर, 2023 के दौरान कर्नाटक कार्यान्वयन एजेंसी के अनुरोध पर कर्नाटक के तीन बांधों (अर्थात् कृष्णराज सागर, अल्माटी बांध और तुंगभद्रा बांध) का दौरा किया और चल रहे बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, चरण- II और III के तहत बांधों की पुनर्वास प्रगति के दौरान कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं के संबंध में परियोजना अधिकारियों के साथ चर्चा की।

मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा (एमएसटीजी) लिंक परियोजना का संयुक्त दौरा

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए), लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए अनुरोध के जवाब में, 19.12.2023 से 23.12.2023 के दौरान एनडब्ल्यूडीए के अधिकारियों के साथ बीसीडी (ई एंड एनई) निदेशालय, के.ज.आ., जीएसआई, कोलकाता, सीएसएमआरएस, नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा एमएसटीजी लिंक परियोजना का एक संयुक्त क्षेत्र दौरा किया गया था।

Sardar Sarovar Dam, Gujarat

I. बाढ़ और संबंधित मामले

देश में बाढ़ की स्थिति-दिसंबर 2023

ब्रह्मपुत्र और बराक और झेलम बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2023 को शुरू हुई। 1 मई से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान, कुल 6339 (4567 स्तर + 1772 प्रवाह) बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए, जिनमें से 5952 (4336 स्तर + 1616 प्रवाह) पूर्वानुमान 93.89% प्रतिशत की सटीकता के साथ अनुमेय सीमा के भीतर थे। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से माह दिसम्बर 2023 में 28 रेड बुलेटिन (चरम बाढ़ की स्थिति के लिए) एवं 18 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किये गये।

01.05.2023 से 31.12.2023 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

चरम बाढ़ की स्थिति

05 एफएफ स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई

क्र. सं.	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1	एनसीटी दिल्ली	उत्तरी दिल्ली	यमुना	दिल्ली रेलवे ब्रिज	12/07/2023	15/07/2023
2	उत्तर प्रदेश	बदायूँ	गंगा	कछलाब्रिज	14/07/2023	15/07/2023
					16/07/2023	22/07/2023
					29/07/2023	01/08/2023
					18/08/2023	20/08/2023
3	असम	शिवसागर	दिखोव	शिवसागर	17/07/2023	17/07/2023
					11/08/2023	12/08/2023
4	तेलंगाना	कुमुराम भीम	वर्धा	सिरपुर नगर	24/07/2023	24/07/2023
					29/07/2023	29/07/2023
5	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम	तीस्ता	मेल्ली	04/10/2023	04/10/2023

61 बाढ़ निगरानी स्टेशन पर अत्यधिक बाढ़ की स्थिति देखी गई।

गंभीर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, और गुजरात में 76 एफएफ स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली, ओड़िशा, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल,तमिलनाडू और आंध्र प्रदेश में 65 निगरानी स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, ओडिशा ,मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडू में 45 एफएफ स्टेशन पर बाढ़ की स्थिति सामान्य से ऊपर देखी गई।

सीमा-रेखा से अधिक प्रवाह वाले जलाशय

आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 79 जलाशयों में उनकी सीमा से अधिक प्राप्त हुआ।

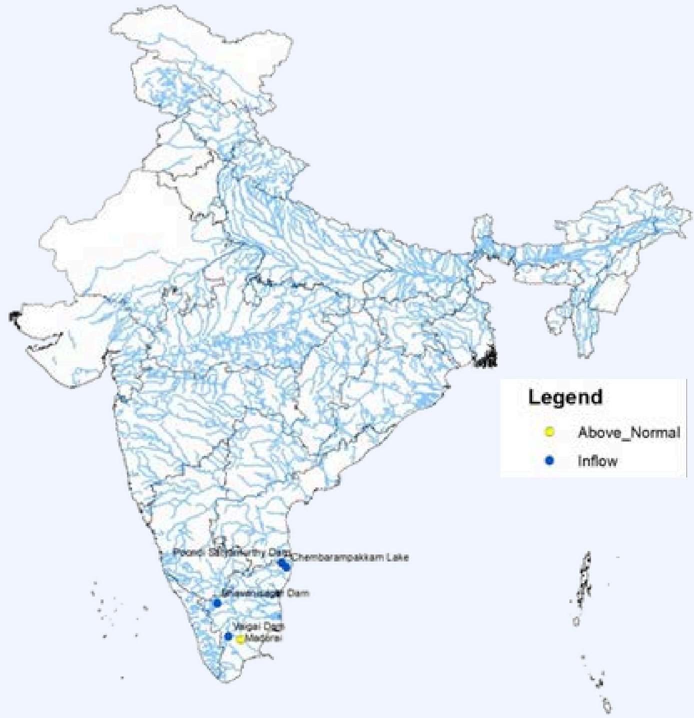

II. अन्य गतिविधियाँ

राज्यों के साथ तीसरी त्रैमासिक वार्ता बैठक

के.ज.आ. ने जल संसाधन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में के.ज.आ. द्वारा किए जा रहे कार्यों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए कार्यों में तालमेल बढ़ाने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन/सिंचाई/जल शक्ति विभाग के साथ बातचीत शुरू की है। तीसरा त्रैमासिक संवाद निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित किया गया था।

महाराष्ट्र

डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र सरकार के साथ संवाद क्षेत्रीय कार्यालय, सीजीडब्ल्यूबी, नागपुर के सहयोग से 29.12.2023 को आयोजित किया गया था। विचार-विमर्श का विषय था "वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन, मुद्दे और समाधान"। इस संबंध में श्री राजीव कुमार, निदेशक, के.ज.आ., नई दिल्ली और उप निदेशक, पीए (सी) द्वारा ऑनलाइन पोर्टल

'ईपीएएमएस' में डीपीआर जमा करने के तरीके पर जोर देने के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया पर एक पीपीटी प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए। राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया गया। सीजीडब्ल्यूबी, नागपुर ने महाराष्ट्र राज्य में भूजल परिदृश्य पर पीपीटी भी प्रस्तुत किया।

गुजरात

श्री के.ए. पटेल, सचिव, डब्ल्यूआरडी, गुजरात और श्री डी.एस. चासकर, मुख्य अभियंता (एमटीबीओ), गांधीनगर की अध्यक्षता में गुजरात राज्य के विभागों के साथ संवाद 29.12.2023 को आयोजित किया गया था। के.ज.आ. के अध्यक्ष द्वारा हाल ही में हुई बैठक के दौरान सामने आए कार्य बिंदुओं के मद्देनजर सरदार सरोवर परियोजना की प्रगति की विशेष रूप से समीक्षा की गई। इसमें सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय कार्यालय, गुजरात के जल संसाधन विभाग, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएनएल), गुजरात जल संसाधन विकास निगम (जीडब्ल्यूआरडीसी) आदि के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में के.ज.आ. और सीजीडब्ल्यूबी द्वारा गुजरात राज्य में किए जा रहे कार्यों पर प्रस्तुति दी गई। भारत सरकार की योजनाओं यानी पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम और आरआरआर के तहत परियोजनाओं से संबंधित मामले की समीक्षा की गई और भौतिक और वित्तीय प्रगति, बाधाओं, परियोजना को पूरा करने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना आदि से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। के.ज.आ. के अध्यक्ष द्वारा हाल ही में हुई बैठक के दौरान सामने आए कार्रवाई बिंदुओं के मद्देनजर सरदार सरोवर परियोजना की प्रगति की विशेष रूप से समीक्षा की गई।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य के विभागों के साथ वार्ता 28.12.2023 को श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता, के.ज.आ., लखनऊ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय कार्यालय और जल संसाधन से संबंधित विभिन्न राज्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश में के.ज.आ. और सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किए जा रहे कार्यों से संबंधित मुद्दों जैसे ई-फ्लो निगरानी, ईएफडब्ल्यूएस, बाढ़ पूर्वानुमान, जल गुणवत्ता निगरानी से संबंधित मुद्दे, एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंतर्गत मैदान, राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र आदि पर विस्तार से चर्चा की गई और भविष्य की कार्रवाई का सुझाव दिया गया।

उत्तराखंड

श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता, के.ज.आ., लखनऊ की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य के विभागों के साथ 27.12.2023 को हाइब्रिड मोड में संवाद वार्ता आयोजित की गयी थी। बैठक में सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय कार्यालय और जल संसाधन से संबंधित विभिन्न राज्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उत्तराखंड में के.ज.आ. और सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किए जा रहे कार्यों जैसे ई-फ्लो मॉनिटरिंग, ईएफडब्ल्यूएस, बाढ़ पूर्वानुमान, बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण, जीएलओएफ, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, भूजल संसाधन आकलन, स्प्रिंग कायाकल्प आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। संवाद में विभागों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपने विचार रखे।

मध्य प्रदेश

दिनांक 18.12.2023 को श्री आदित्य शर्मा, मुख्य अभियंता (एनबीओ), भोपाल की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य के विभागों के साथ संवाद आयोजित किया गया था। इसमें सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में के.ज.आ. और सीजीडब्ल्यूबी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में किये जा रहे कार्यों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। भारत सरकार की योजनाओं से संबंधित मामलों के अलावा, डेटा विनिमय और डेटा साझाकरण के विशिष्ट मुद्दों, क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य सरकार के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किये और इस पहल की सराहना की।

मणिपुर के विधायक श्री रामेश्वर सिंह से मुलाकात

के.ज.आ. के अध्यक्ष ने "मणिपुर में सेकमई नदी के किनारे बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी कार्यों" पर संकल्पना नोट के संबंध में मणिपुर के विधायक श्री रामेश्वर सिंह के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में बताया गया कि कॉन्सेप्ट नोट में सेकमाई नदी के लिए संरचनात्मक उपायों के माध्यम से बाढ़ सुरक्षा और रिवरफ्रंट विकास से संबंधित कार्य शामिल हैं। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि के.ज.आ. दिशानिर्देशों के अनुसार डीपीआर अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है और इसे केवल संरचनात्मक उपायों के माध्यम से बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्यों की परिकल्पना करते हुए तैयार किया जाना चाहिए। चर्चा के बाद संक्षेप में बताया गया कि डीपीआर के.ज.आ. दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया जा सकता है और ई-पीएएमएस के माध्यम से के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

पीएमकेएसवाई, एआईबीपी/सीएडीडब्ल्यूएम योजनाओं के पुनरुद्धार हेतु कार्य समूह की रिपोर्ट पर बैठक

के.ज.आ. के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 13.12.2023 को हाइब्रिड मोड में चल रही पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं की समीक्षा के लिए गठित समिति की पहली बैठक की।

बैठक में मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा सरकार, नीति आयोग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अधिकारियों और के.ज.आ. (मुख्यालय) और क्षेत्रीय संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा राज्यों के अधिकारियों ने अपनी परियोजनाओं की स्थिति प्रस्तुत की। चल रही पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी एंड डब्लूएम परियोजनाओं की प्रगति, मार्च, 2026 से पहले उनके पूरा होने की संभावना, मुद्दों और बाधाओं और इन बाधाओं को हल करने के रास्ते के साथ-साथ जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा परिकल्पित नई सीएडी एंड डब्लूएम योजना में उन पीएमकेएसवाई परियोजनाओं के सीएडी एंड डब्लूएम घटक को लेने पर विस्तृत चर्चा की गई।

के.ज.आ. के अध्यक्ष ने राज्य के अधिकारियों को मामले में निर्णय लेने के लिए अगली बैठक के दौरान परियोजनाओं की पूरी योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सैटेलाइट डेटा के उपयोग पर प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक

जल संसाधनों में RISAT-1A, 1B, रिसोर्ससैट-3A और रिसोर्ससैट-3SA से उपग्रह डेटा के उपयोग के लिए DoWR, RD&GR (जल शक्ति मंत्रालय) और अंतरिक्ष विभाग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। डीओ डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, के.ज.आ. के अनुमोदन से, कार्यालय आदेश दिनांक 19.01.2023 के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में उपग्रह डेटा के उपयोग के लिए तीन कार्य समूहों का गठन किया गया था, जो निम्नानुसार हैं:

1. बाढ़ और आपदा प्रबंधन के लिए कार्य समूह, ए
2. जल संसाधन योजना पर कार्य समूह बी
3. मानचित्रण संबंधी गतिविधियों पर कार्य समूह सी

केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 18 दिसंबर 2023 को हाइब्रिड मोड में रिसैट-1ए, रिसैट-1बी, रिसोर्ससैट-3ए और रिसोर्ससैट-3एसए डेटा के उपयोग पर प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की।

बैठक में के.ज.आ.-मुख्यालय, एनआरएससी, एमआई स्टेट विंग (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) आदि के विभिन्न अधिकारियों ने भाग लिया। समीक्षा बैठक के दौरान, 3 कार्य समूहों को शामिल करने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्य योजना, प्रगति की स्थिति, बाधाओं और भविष्य की कार्रवाई जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए उपग्रह डेटा उपयोग के लिए कार्य योजना के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने केंद्र और राज्य सरकारों के तहत विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यों के दोहराव को खत्म करने और विदेशी उपग्रहों पर निर्भरता को कम करने और उपग्रह डेटा उपयोग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया।

III. राजभाषा संबन्धित

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग और भारत सरकार के पदेन सचिव की अध्यक्षता में, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 154वीं बैठक दिनांक 20.12.2023 को आयोजित की गई। उक्त बैठक में अध्यक्ष, के.ज.आ. महोदय द्वारा आयोग में पिछली तिमाही में हुई राजभाषाई प्रगति की समीक्षा की गई। अध्यक्ष, के.ज.आ. महोदय ने आयोग में राजभाषा नीति एवं नियमों के पालन किए जाने तथा हिन्दी में मूल पत्राचार शत-प्रतिशत हिन्दी में करने का निदेश दिया।

एनएबीएल मान्यता प्राप्त जल गुणवत्ता प्रयोगशाला

के.ज.आ. में स्थित जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की सूची

क्रम सं.	प्रयोगशाला का स्थान	प्रयोगशाला का स्तर	संगठन
1	राष्ट्रीय नदी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, नई दिल्ली	तृतीय	यमुना बेसिन संगठन, नई दिल्ली
2	निचली कावेरी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, कोयंबटूर	तृतीय	कावेरी एवं दक्षिण नदियां संगठन, कोयंबटूर
3	ऊपरी और मध्य गंगा जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, वाराणसी	तृतीय	निचली गंगा बेसिन संगठन, पटना
4	कृष्णा और गोदावरी नदी जल गुणवत्ता, हैदराबाद	तृतीय	कृष्णा और गोदावरी बेसिन संगठन, हैदराबाद
5	ऊपरी कावेरी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, बैंगलोर	द्वितीय	प्रबोधन दक्षिण संगठन, बैंगलोर
6	दक्षिण पश्चिम बहती नदियां जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, कोच्चि	द्वितीय	कावेरी एवं दक्षिण नदियां संगठन, कोयंबटूर
7	ऊपरी कृष्णा मंडल जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, पुणे	द्वितीय	कृष्णा और गोदावरी बेसिन संगठन, हैदराबाद
8	माही मंडल जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, गांधीनगर	द्वितीय	माही तापी बेसिन संगठन, गांधीनगर
9	निचली यमुना जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, आगरा	द्वितीय	यमुना बेसिन संगठन, नई दिल्ली
10	पूर्वी नदियाँ जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, भुवनेश्वर	द्वितीय	महानदी एवं पूर्वी नदियां संगठन, भुवनेश्वर
11	जल विज्ञान मंडल, चेन्नई	द्वितीय	कावेरी एवं दक्षिण नदियां संगठन, कोयंबटूर
12	वैनगंगा मंडल, नागपुर	द्वितीय	प्रबोधन मध्य संगठन, नागपुर
१३	चिनाब मंडल, जम्मू	द्वितीय	सिंधु बेसिन संगठन, चंडीगढ़
14	मध्य गंगा मंडल -I, लखनऊ	द्वितीय	ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, लखनऊ
15	महानदी मंडल, रायपुर	द्वितीय	महानदी एवं पूर्वी नदियां संगठन, भुवनेश्वर
16	मध्य ब्रह्मपुत्र मंडल, गुवाहाटी	तृतीय	ब्रह्मपुत्र बेसिन संगठन, गुवाहाटी
17	निचली ब्रह्मपुत्र मंडल, जलपाईगुड़ी	द्वितीय	तीस्ता एवं भागीरथी दामोदर बेसिन संगठन, कोलकाता
18	ऊपरी ब्रह्मपुत्र मंडल, डिब्रूगढ़	द्वितीय	ब्रह्मपुत्र बेसिन संगठन, गुवाहाटी
19	निचली गंगा मंडल, बरहामपुर	द्वितीय	तीस्ता एवं भागीरथी दामोदर बेसिन संगठन, कोलकाता
20	मध्य गंगा मंडल-5, पटना	द्वितीय	निचली गंगा बेसिन संगठन, पटना
21	नर्मदा मंडल, भोपाल	द्वितीय	नर्मदा बेसिन संगठन, भोपाल
22	तापी मंडल, सूरत	द्वितीय	माही तापी बेसिन संगठन, गांधीनगर
23	हिमालयन गंगा मंडल, देहरादून	द्वितीय	ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, लखनऊ

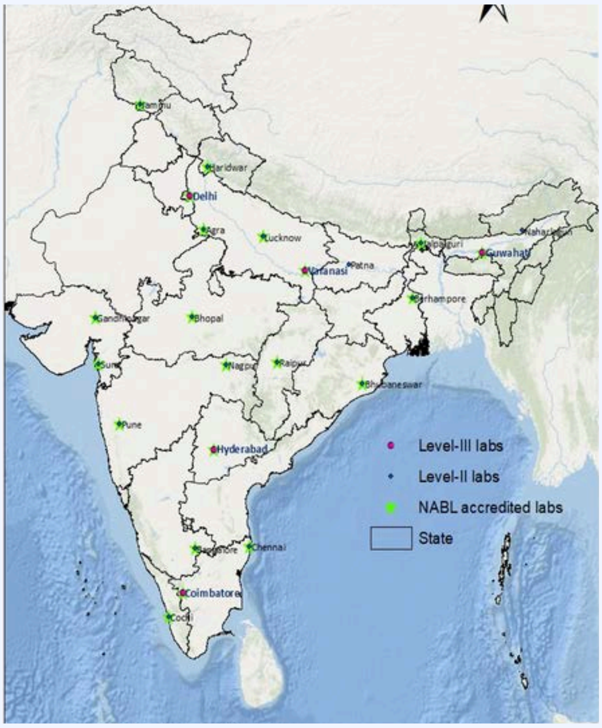

हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

दिनांक 13.12.2023 को केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें श्री अरविंद पारिख, सहायक निदेशक (रा.भा.), सेवानिवृत्त द्वारा "कंप्यूटर में हिन्दी अनुप्रयोग" विषय पर व्याख्यान दिया गया। इस कार्यशाला में व्याख्याता द्वारा आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर में हिन्दी अनुप्रयोगों के विभिन्न पहलुओं एवं इसके महत्व से अवगत कराया गया।

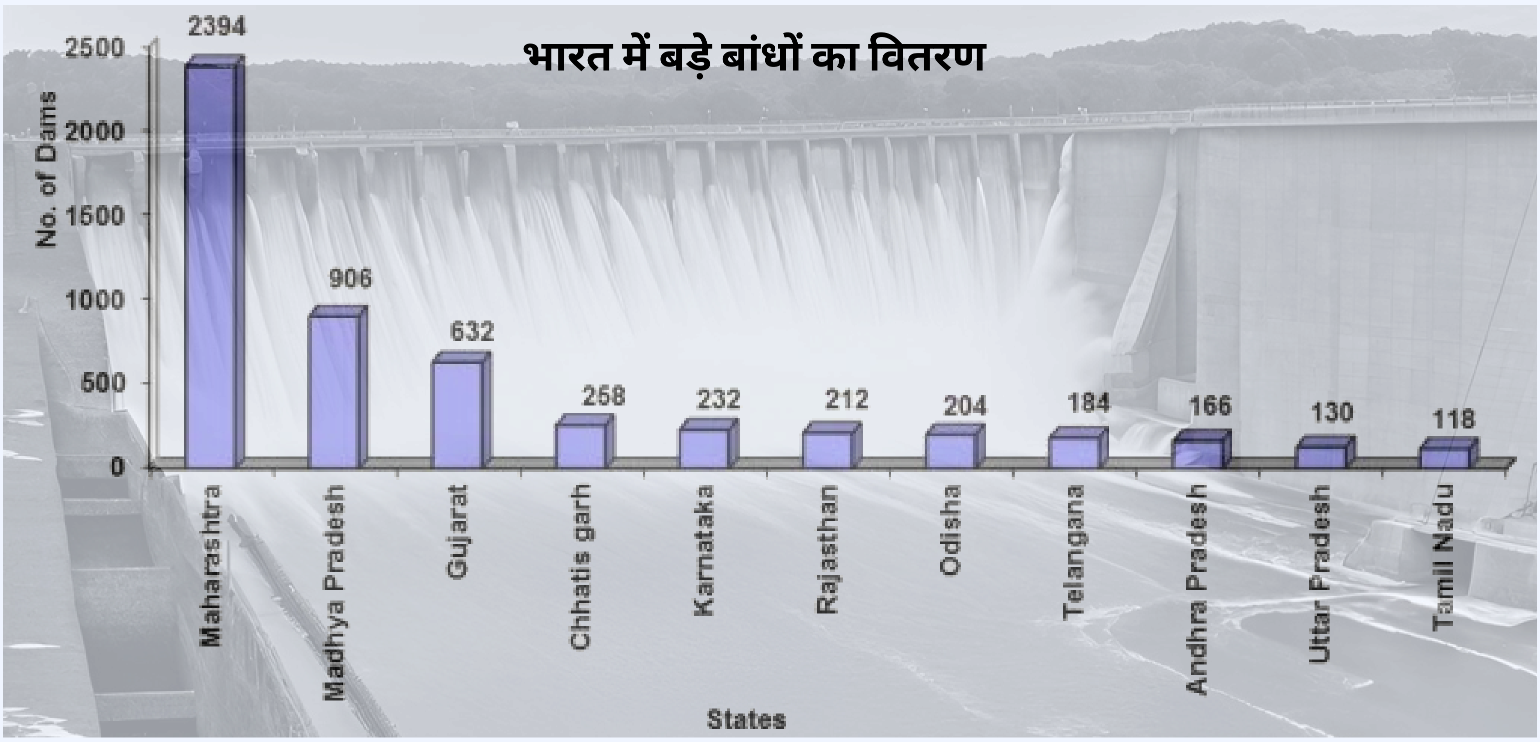

IV. जलाशय निगरानी

के.ज.आ. साप्ताहिक आधार पर देश के 150 जलाशयों की लाइव स्टोरेज स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 35.299 बीसीएम है। इन 150 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 178.784 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित भंडारण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 69.35% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 28.12.2023 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 107.707 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 60% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण 134.119 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 114.961 बीसीएम था। इस प्रकार, 28.12.2023 बुलेटिन के अनुसार 150 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रहण का 80% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 94% है।

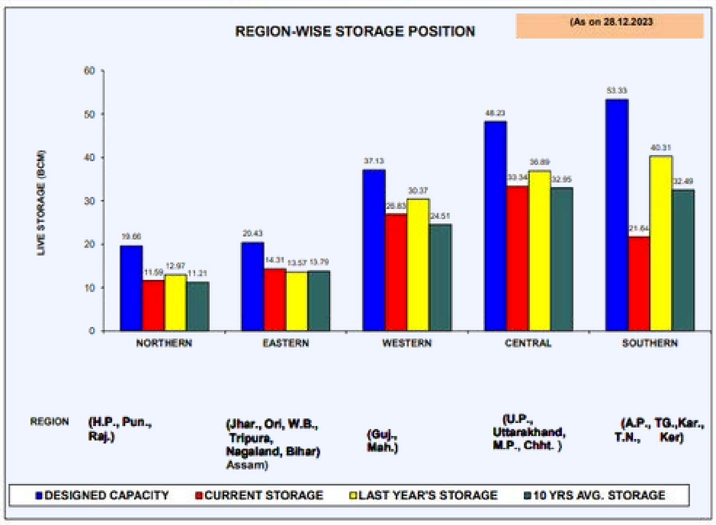

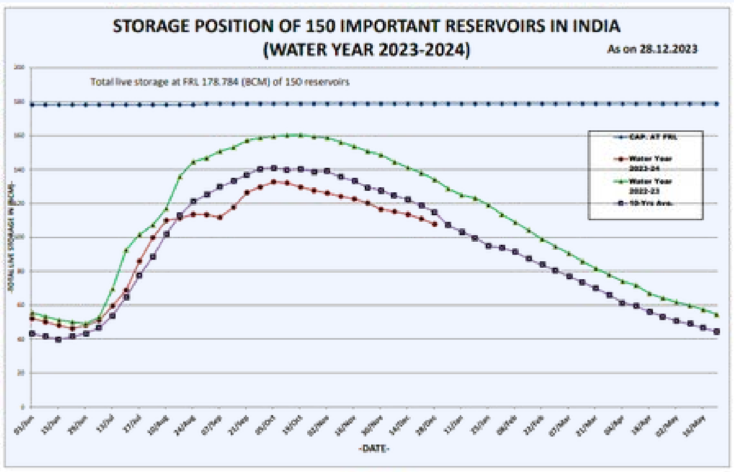

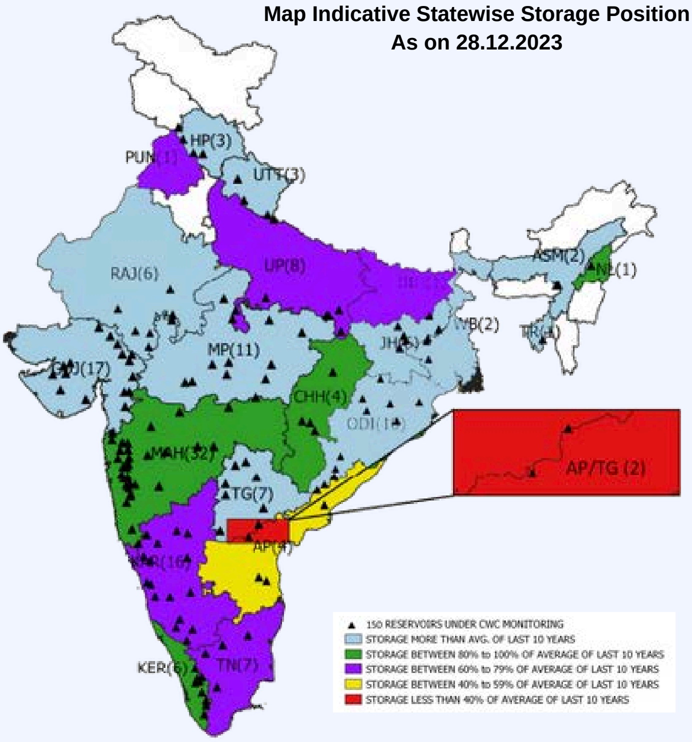

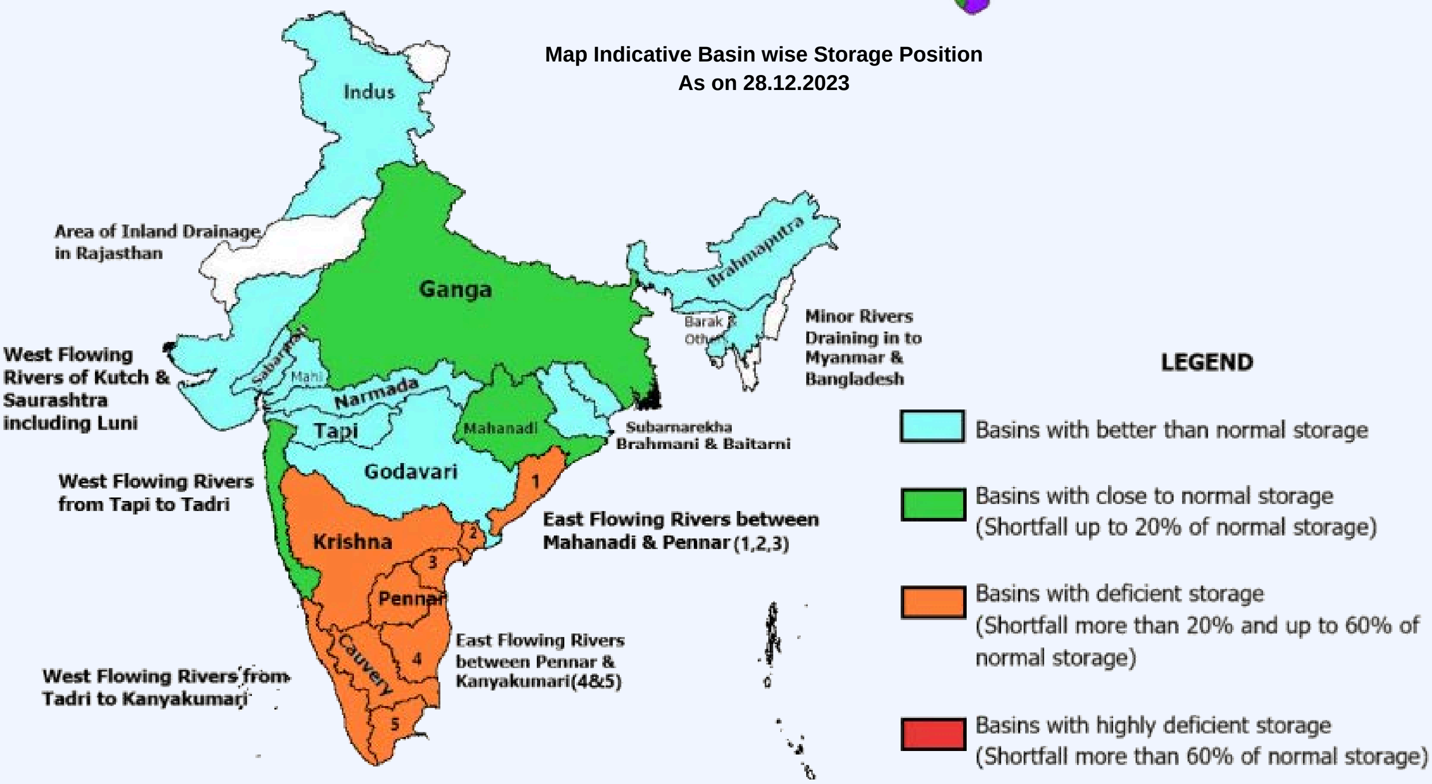

गैलरी

श्री मोहम्मद फैज़ सैयद, निदेशक जलविज्ञान (शहरी) ने 07.12.2023 को मुख्य अभियंता, I&FC के कक्ष में श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता, I&FC, जोन1 और I&FC के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक का एजेंडा तटबंध विवरण, आवश्यक और मुख्य विशेषताएं/निकासों के लेआउट को बढ़ाने से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करना था।

जापान में 2-16 दिसंबर 2023 के दौरान जेआईसीए, त्सुकुबा केंद्र में एकीकृत जल प्रबंधन पर जानकारी के संबंध में ज्ञान सह-निर्माण कार्यक्रम (कंट्रीफोकस)

प्रबोधन मध्य संगठन, केंद्रीय जल आयोग, नागपुर द्वारा दिनांक 22.12.2023 को मुख्य अभियंता श्री. नीरज कुमार मांगलिक की अध्यक्षता में एक हिंदी व्याख्यान का आयोजन किया गया जिसमें डॉ अमित नाफडे, आयुर्वेदाचार्य तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीजीएचएस, नागपुर द्वारा " हृदय रोग के कारण और बचाव" पर सारगर्भित व्याख्यान दिया गया।

तकनीकी सलाहकार सह-कार्यकारी समिति (उत्तर) क्षेत्र की 8वीं बैठक 23.11.2023 को निगरानी (दक्षिण) संगठन, सीडब्ल्यूसी, बेंगलुरु में हुई, जिसमें केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-एसएमआई के तहत प्रस्तावित यादगीर जिले से संबंधित 31 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर चर्चा की गई।

माही एवं तापी बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, गांधीनगर द्वारा हिन्दी कार्यशाला का आयोजन "वित्तीय प्रबंधन तथा भाषा एवं संस्कृति के परिपेक्ष्य में राजभाषा कार्यान्वयन" विषय पर मुख्य अभियंता महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19.12.2023 को संपन्न हुआ ।

दिनांक 15-12-2023 को माही व तापी बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, गांधनगर द्वारा 2023 के बाढ़ पूर्वानुमान व्यवस्था की समीक्षा के लिए पोस्ट मानसून अंतरराज्यीय बैठक (तापी, नर्मदा, दमन गंगा बेसिन की) हाईब्रिड माध्यम से (आनलाइन एवं आफलाइन) मुख्य अभियंता, माही एवं तापी बेसिन संगठन केंद्रीय जल आयोग, गांधीनगर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- डॉ. बी.आर.के. पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री राकेश टोटेजा, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री सुनीलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in

No. CWC/2025/41 | cwc.gov.in | /CWCOfficial.GoI | /CWCOfficial.Go | /CWCOfficial_GoI | c/CWCOfficialGoI